भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5850
उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

डिजिटल शिक्षण पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रभाव

5850. **श्री आदित्य यादवः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, उपकरणों की कमी और प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण में शिक्षकों की अक्षमता के कारण डिजिटल शिक्षण के प्रयास निष्प्रभावी हैं जिससे शहरी-ग्रामीण डिजिटल अंतराल बढ़ रहा है और आधुनिक शैक्षिक संसाधनों तक छात्रों की पहुंच सीमित हो रही है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने, किफायती उपकरण उपलब्ध कराने, संरचित प्रशिक्षण और सहायता के माध्यम से शिक्षकों का क्षमता निर्माण करने और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के प्रशासन के अधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अधिगम को बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल का कार्यान्वयन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बदायूँ जिले में डिजिटल शिक्षण को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है। डिजिटल अंतर का समाधान करने के लिए डिजिटल अधिगम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बदायूँ जिले में डिजिटल शिक्षण को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है। डिजिटल अंतर का समाधान करने के लिए डिजिटल अधिगम अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत कदम उठाए गए हैं। बदायूँ जिले में 36 पीएम श्री स्कूल (सरकारी: 34, केविसं: 1 और नविस: 1) हैं। इन 36 में से 17 प्राथमिक, 13 उच्च प्राथमिक और 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। राज्य के सभी स्कूलों को इंटरनेट सुविधा से सुसज्जित टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। इन डिजिटल व्यवस्थाओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता की है। समग्र शिक्षा के माध्यम से बदायूँ जिले में 25 आईसीटी लैब, 17 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं।

भारत सरकार ने बजट वर्ष 2025 में बीएसएनएल द्वारा चरणबद्ध तरीके से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा के प्रावधान की घोषणा की है। स्मार्ट कक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु इंटरनेट सुविधा के लिए वार्षिक आधार पर प्रति स्कूल 12,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

समग्र शिक्षा के अतिरिक्त, राज्य अलंकार परियोजना (एक राज्य पहल) के माध्यम से स्कूलों में अवसंरचना को भी सुदृढ़ कर रहा है। कक्षाओं में डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, डिजिटल अधिगम के लिए दीक्षा मंच और पीएम ईविद्या के उपयोग के लिए सहयोग भी प्रदान किया जाता है।

शिक्षकों को ई-सामग्री के उपयोग, डिजिटल शिक्षाशास्त्र, कक्षाओं में आईसीटी के प्रभावी उपयोग, स्मार्ट उपकरणों और साइबर सुरक्षा संबंधी एससीईआरटी द्वारा संचालित कार्यक्रमों और दीक्षा जैसे मंचों के माध्यम से नियमित आधार पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से प्रशिक्षित भी किया जाता है।

******